



# SAFALTA CLASS<sup>TM</sup>

An Initiative by **अमरउजाला**

# INDIAN POLITY BY- SUJEET BAJPAI SIR



संविधान में (X)

## BUDGET IN PARLIAMENT

Art: (112)

वित्तिक विवरण पत्रिका

The Constitution refers to the budget as the ('annual financial statement') In other words, the term 'budget' has nowhere been used in the Constitution. It is the popular name for the 'annual financial statement' that has been dealt with in Article 112 of the Constitution.

# संसद में बजट

संविधान ने बजट को 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा है। दूसरे शब्दों में, 'बजट' शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' का प्रचलित नाम है तथा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है।

## Funds

निधियाँ

The Constitution of India provides for the following three kinds of funds for the Central government:

1. Consolidated Fund of India (Article 266)
2. Public Account of India (Article 266)
3. Contingency Fund of India (Article 267)



## निधियां —

भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए निम्नलिखित तीन प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है:

1. भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 266) ।
2. भारत का लोकलेखा (अनुच्छेद 266) ।
3. भारत की आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267) ।

## Whip

Though the offices of the leader of the House and the leader of the Opposition are not mentioned in the Constitution of India, they are mentioned in the Rules of the House and Parliamentary Statute respectively.

## सचेतक

यद्यपि सभा के नेता और विपक्ष के नेता के कार्यालयों का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन उनका उल्लेख क्रमशः सभा और संसदीय कानून के नियमों में किया गया है ।

The members are supposed to follow the directives given by the whip. Otherwise, disciplinary action can be taken.\

सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सचेतक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें ।

अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।



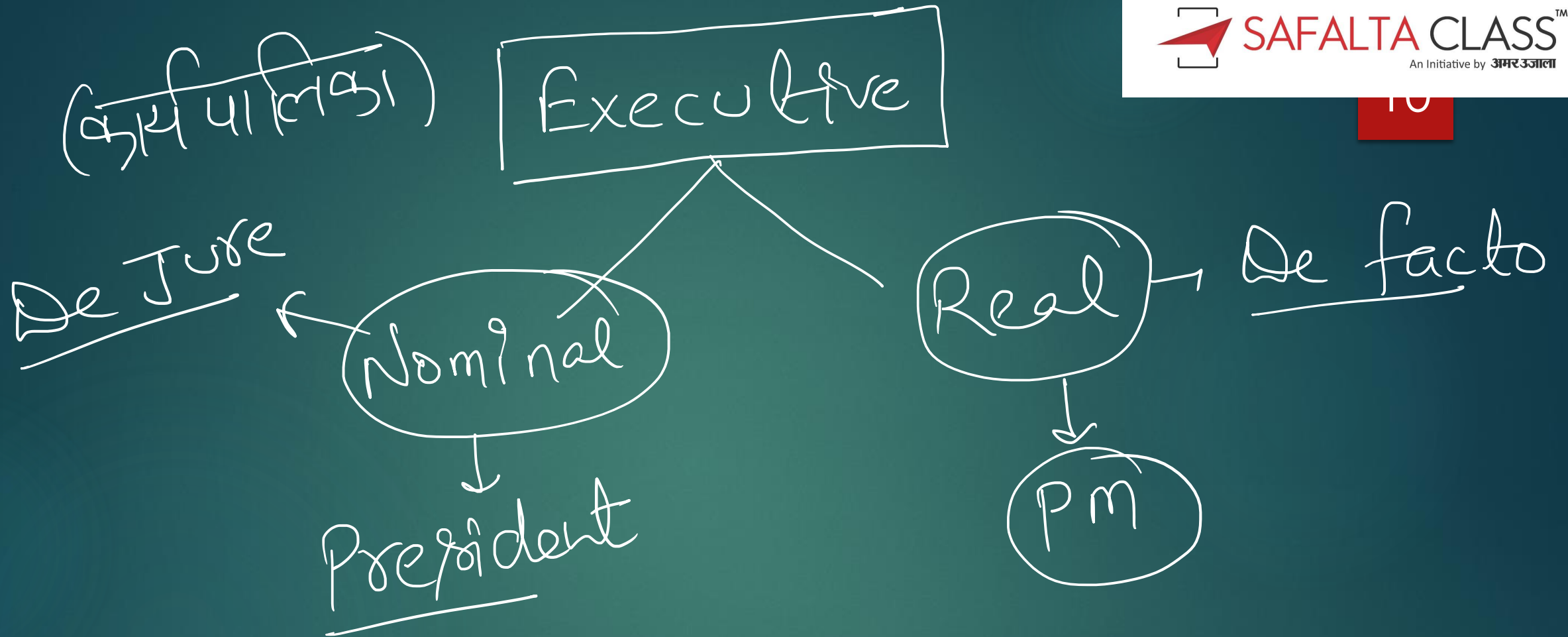
# President of India



सत्यमेव जयते

कार्यपालिका

Art - (52)  
Presi.  
Art - (53)  
Head of  
executive



# Presidents of India

निर्वाचित



1950 to 1962

Rajendra  
Prasad



1962 to 1967

Sarvepalli  
Radhakrishnan



1982 to 1987

Giani Zail  
Singh



1977 to 1982

Neelam  
Sanjiva Reddy



1974 to 1977

Fakhruddin  
Ali Ahmed



1969 to 1974

Varahagiri  
Venkata Giri



1967 to 1969

Zakir  
Hussain



1987 to 1992

Ramaswamy  
Venkataraman



1992 to 1997

Shankar  
Dayal Sharma



1997 to 2002

K R  
Narayanan



2002 to 2007

APJ  
Abdul Kalam



2007 to 2012

Pratibha  
Patil



2017 to Present

Ram Nath  
Kovind



2012 to 2017

Pranab  
Mukherjee

पुथन दलित

पद पर  
रही  
थी  
Seetha  
पहली  
नरिनी

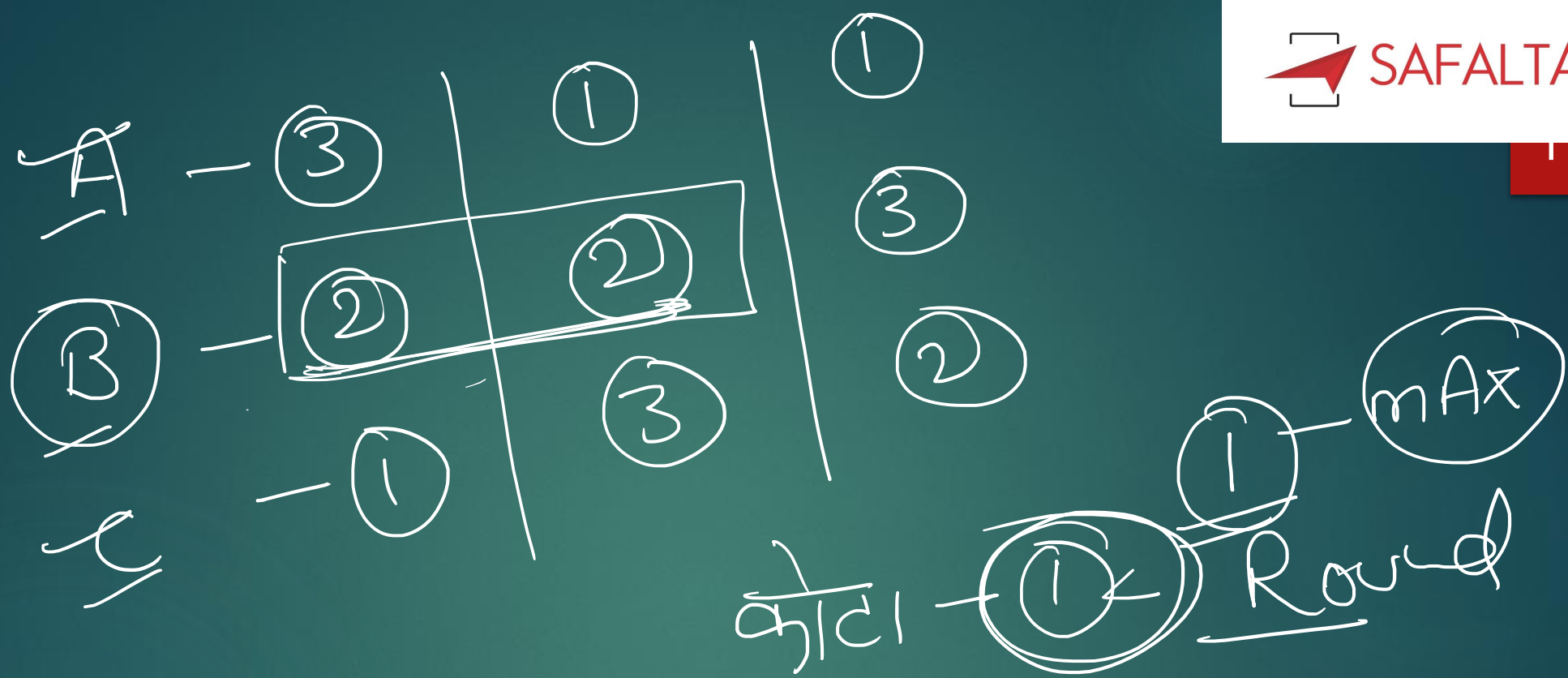


The President is the head of the Indian State. He is the first citizen of India and acts as the symbol of unity, integrity and solidarity of the nation.

राष्ट्रपति भारतीय राज्य के प्रमुख हैं। वह भारत के प्रथम नागरिक हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं।

# HOW IS OUR PRESIDENT ELECTED?







The President's election is held in accordance with the **system** of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting is by secret ballot.

This system ensures that the successful candidate is returned by the absolute majority of votes.

{ राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है । }

यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सफल उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत से वापस किया जाए ।



The President is elected not directly by the people but by members of electoral college consisting of:

1. the elected members of both the Houses of Parliament;
2. the elected members of the legislative assemblies of the states; and
3. the elected members of the legislative assemblies of the Union Territories of Delhi, Jammu & Kashmir and Puducherry.

राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है जिसमें शामिल हैं:

1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य;
2. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य; और
3. दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

## Qualifications for Election as President

A person to be eligible for election as President should fulfil the following qualifications:

1. He should be a citizen of India.
2. He should have completed 35 years of age.
3. He should be qualified for election as a member of the Lok Sabha.

राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना चाहिए:

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए थी।
3. उसे लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए।

$$100 \times \frac{1}{6} = \rightarrow$$

The nomination of a candidate for election to the office of President must be subscribed by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders. — अनुसूची ६९

Every candidate has to make a security deposit of Rs 15,000 in the Reserve Bank of India.

राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन में प्रस्तावक के रूप में कम से ५० निर्वाचकों और ५० निर्वाचकों को सेटर के रूप में सदस्यता लेनी चाहिए।

हर उम्मीदवार को (भारतीय रिजर्व बैंक) में 15,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी।

RBI



The security deposit is liable to be forfeited in case the candidate fails to secure one-sixth of the votes polled.

21

Before 1997, number of proposers and seconders was ten each and the amount of security deposit was Rs 2,500.

In 1997, they were increased to discourage the non-serious candidates.

यदि उम्मीदवार डाले गए मतों का छठा हिस्सा सुरक्षित करने में विफल रहता है तो सुरक्षा जमा को अग्रक्षित किया जा सकता है ।

1997 से पहले, प्रस्तावकों और सेकेंडरों की संख्या दस थी और सुरक्षा जमा की राशि 2,500 रुपये थी।

१९९७ में उन्हें गैर गंभीर उम्मीदवारों को हतोत्साहित करने के लिए बढ़ा दिया गया ।

# महाभियोग - Art-61



— आधार -  
सिद्धि का  
उल्लंघन

The President can be removed from office by a process of impeachment for 'violation of the Constitution'.

However, the Constitution does not define the meaning of the phrase 'violation of the Constitution'.

संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है ।

हालांकि, संविधान में संविधान के उल्लंघन के वाक्यांश के अर्थ को परिभाषित नहीं किया गया है ।

LS/RS

# Procedure of Impeachment



1

- A written notice signed by more than  $\frac{1}{4}^{\text{th}}$  of the total number of members of the House (any) is submitted. Once it is received, after 14 days a Resolution is moved.

2

- The Resolution is passed by majority i.e. more than  $\frac{2}{3}^{\text{rd}}$  of the total members of the House.

3 & 4

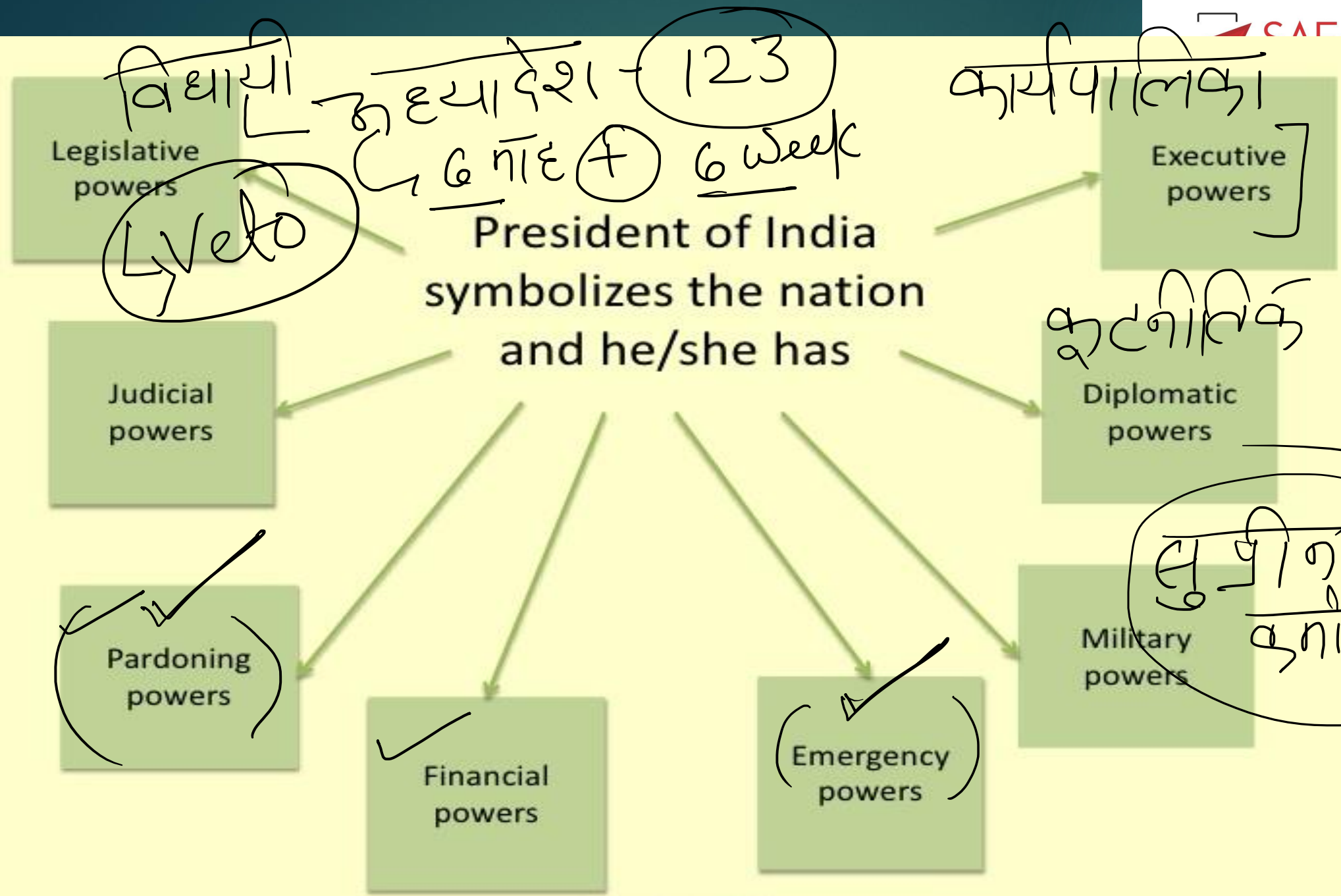
- The charge is sent to the other house for investigation. President needs to be present for the investigation.
- After the investigation, if the charge is proved right and passed by  $\frac{2}{3}^{\text{rd}}$  of the total members of the house (which investigated) then the President is removed.

जाँच

24

LS/RS





सुप्रीम कोर्ट

## Executive Powers

The executive powers and functions of the President are:

1. All executive actions of the Government of India are formally taken in his name.

कार्यकारी शक्तियां

राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां और कार्य हैं:

1. भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से उनके नाम पर किए जाते हैं।



2. He appoints the prime minister and the other ministers. They hold office during his pleasure.

3. He appoints the attorney general of India and determines his remuneration.

The attorney general holds office during the pleasure of the President.

2. वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं । वे अपनी खुशी के दौरान पद धारण करते हैं ।

3. वह भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति की खुशी के दौरान पद धारण करते हैं ।

4. He appoints the comptroller and auditor general of India, the chief election commissioner and other election commissioners, the chairman and members of the Union Public Service Commission, the governors of states, the chairman and members of finance commission, and so on.

4. वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्यों के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है।

# Legislative Powers

1. He can summon or prorogue the Parliament and dissolve the Lok Sabha.

He can also summon a joint sitting of both the Houses of Parliament, which is presided over by the Speaker of the Lok Sabha.

## विधायी शक्तियां

1. वह संसद को बुला सकता है या उसका प्रस्ताव कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है।

वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

2. He can address the Parliament at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year.

3. He nominates 12 members of the Rajya Sabha from amongst persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art and social service.

2. वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में संसद को संबोधित कर सकते हैं और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र ।

3. वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।



# Financial Powers

The financial powers and functions of the President are:

1. Money bills can be introduced in the Parliament only with his prior recommendation.
2. He causes to be laid before the Parliament the annual financial statement (ie, the Union Budget).

राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां और कार्य हैं:

1. धन विधेयकों को संसद में केवल उनकी पूर्व सिफारिश के साथ पेश किया जा सकता है।
2. वह संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (यानी, केंद्रीय बजट) प्रस्तुत करने का कारण बनता है।

3. He constitutes a finance commission after every five years to recommend the distribution of revenues between the Centre and the states.

3. वह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए हर पांच साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है।

# Judicial Powers

1. He appoints the Chief Justice and the judges of Supreme Court and high courts.

2. He can seek advice from the Supreme Court on any question of law or fact.

However, the advice tendered by the Supreme Court is not binding on the President.

## न्यायिक शक्तियां

1. वह मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
  2. वह कानून या तथ्य के किसी भी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं।
- हालांकि, उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है ।



3. He can grant pardon, reprieve, respite and remission of punishment, or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence.

3. वह किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, राहत, राहत और छूट, या निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकता है।

## Diplomatic Powers

The international treaties and agreements are negotiated and concluded on behalf of the President.

राजनयिक शक्तियां राष्ट्रपति की ओर से अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर बातचीत और निष्कर्ष निकाला जाता है ।

## Military Powers

He is the supreme commander of the defence forces of India.

In that capacity, he appoints the chiefs of the Army, the Navy and the Air Force. He can declare war or conclude peace, subject to the approval of the Parliament.

सैन्य शक्तियां वह भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं।  
उस हैसियत से वह सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की  
नियुक्ति करता है।

वह युद्ध की घोषणा कर सकता है या संसद के अनुमोदन के अध  
लिए शांति समाप्त कर सकता है ।

# National Emergency in India



## Emergency Powers

In addition to the normal powers mentioned above, the Constitution confers extraordinary powers on the President to deal with the following three types of emergencies:

- (a) National Emergency (Article 352);
- (b) President's Rule (Article 356 & 365); and
- (c) Financial Emergency (Article 360)

No

## आपातकालीन शक्तियां

उपर्युक्त सामान्य शक्तियों के अलावा, संविधान राष्ट्रपति को निम्नलिखित तीन प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने के लिए असाधारण शक्तियां प्रदान करता है:

- (क) राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352);
- (ख) राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356 और 365); और
- (ग) वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

The Emergency provisions are contained in Part XVIII of the Constitution, from Articles 352 to 360.

These provisions enable the Central government to meet any abnormal situation effectively.

आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद ३५२ से ३६० तक निहित हैं ।

ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं।

1.

[An emergency due to <sup>①</sup>war, <sup>②</sup>(external aggression) or <sup>③</sup>(armed rebellion) (Article 352).]

This is popularly known as 'National Emergency'.

However, the Constitution employs the expression 'proclamation of emergency' to denote an emergency of this type.

Armed Rebellion (हथियार - x)  
 , शक्ति - अशानि

1. युद्ध, बाहरी आक्रामकता या सशस्त्र विद्रोह (अनुच्छेद 352) के कारण आपातकाल। इसे 'राष्ट्रीय आपातकाल' के नाम से जाना जाता है।

हालांकि, संविधान इस प्रकार की आपात स्थिति को निरूपित करने के लिए ' आपातकाल की उद्घोषणा ' की अभिव्यक्ति को नियोजित करता है ।



Originally, the Constitution mentioned 'internal disturbance' as the third ground for the proclamation of a National Emergency, but the expression was too vague and had a wider connotation.

Hence, the 44th Amendment Act of 1978 substituted the words 'armed rebellion' for 'internal disturbance'.

मूल रूप से, संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए तीसरे आधार के रूप में आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया था, लेकिन अभिव्यक्ति बहुत अस्पष्ट थी और इसका व्यापक अर्थ था। इसलिए, 1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम ने आंतरिक अशांति के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्दों को प्रतिस्थापित किया।

Thus, it is no longer possible to declare a National Emergency on the ground of 'internal disturbance' as was done in 1975 by the Congress government headed by Indira Gandhi.

इस प्रकार, अब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना संभव नहीं है जैसा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा १९७५ में किया गया था ।

## Parliamentary Approval and Duration

The proclamation of Emergency must be approved by both the Houses of Parliament within one month from the date of its issue.

संसद अनुमोदन और अवधि आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने मुद्दे की तारीख से एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए ।

If approved by both the Houses of Parliament, the emergency continues for six months, and can be extended to an indefinite period with an approval of the Parliament for every six months.

यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आपातकाल छह महीने तक जारी रहता है और इसे प्रत्येक छह महीने के लिए संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित अवधि तक बढ़ाया जा सकता है ।



## Effect on the Fundamental Rights

Articles 358 and 359 describe the effect of a National Emergency on the Fundamental Rights.

Article 358 deals with the suspension of the Fundamental Rights guaranteed by Article 19, while Article 359 deals with the suspension of other Fundamental Rights (except those guaranteed by Articles 20 and 21).

मौलिक अधिकारों पर प्रभाव अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं।

अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीशुदा मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) ।

Declarations Made So Far This type of Emergency has been proclaimed three times so far—

1. 1962 — Indo - china War  
Pak

2. 1971 —

3. 1975.

Internal disturbance

बिना  
शांति